



मकरसंक्रांति पर जल महल की पाल पर आयोजित पतंग उत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तथा उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने किया। इस अवसर पर पर्यटकों के लिये सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ।

मुख्यमंत्री भजनलाल ने जल महल की पाल पर पतंग उड़ाई

उन्होंने व उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने पर्यटन विभाग के 'काईट फेस्टिवल' का उद्घाटन किया

जयपुर, 14 जनवरी। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर जयपुर के जल महल की पाल पर आयोजित "काईट फेस्टिवल" ने राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर और पर्यटकों को एक नया आयाम दिया। यह आयोजन न केवल पतंगबाजी का जश्न था, बल्कि पारंपरिक कला, संगीत और भोजन का अद्भुत संगम भी रहा।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने इस आयोजन का उद्घाटन गुब्बारे उड़ान कर किया। पतंगबाजी के रोमांच ने पूरे आयोजन को विशेष बना दिया। जल महल के आसमान में रंग-बिरंगी पतंगों ने उत्सव के माहौल को जीवंत कर दिया। पतंग बनाने की पारंपरिक कला का लाइव प्रदर्शन भी किया गया, जिसने बच्चों और पर्यटकों को बहुत आकर्षित किया।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने पतंग प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने घोषणा की कि आने वाले वर्षों में इस उत्सव को

उन्होंने कहा कि जयपुर का यह उत्सव राजस्थान की सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है और देश-विदेश के पर्यटकों को यहां की समृद्धि से परिचित कराता है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन राज्य की परंपराओं और समृद्धि को विश्व पटल पर प्रस्तुत करने का एक अच्छा अवसर है।

इस आयोजन में लोक कला और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। लंगा गायन, कालबेलिया नृत्य, मधुर नृत्य और भंगम वादन जैसे

तीसरी पीढ़ी की गाइडेड मिसाइल का सफल मूल्यांकन परीक्षण

जैसलमेर, 14, जनवरी (नि.सं.)। पोकरण फोल्ड रेंज में भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की "पंटी-टैक फायर-एंड-फॉरगेट" गाइडेड मिसाइल, नाग एमके 2 के फोल्ड मूल्यांकन परीक्षण सफलतापूर्वक किए गए। तीन फोल्ड परीक्षणों के दौरान, मिसाइल प्रणालियों ने सभी लक्ष्यों को सटीक रूप से नष्ट कर दिया - अधिकतम और न्यूनतम सीमा, इस प्रकार इसकी फायरिंग रेंज को मान्य किया गया।

नाग मिसाइल कैरियर वर्जन-2 का यह मिसाइल अब भारतीय सेना में शामिल होने के लिये तैयार है।

थी फोल्ड मूल्यांकन किया गया। इसके साथ ही, अब पूरी हथियार प्रणाली भारतीय सेना में शामिल होने के लिए तैयार है। राजनाथ सिंह ने नाग एमके 2 की संपूर्ण हथियार प्रणाली के सफल क्षेत्र मूल्यांकन परीक्षणों के लिए डीआरडीओ, भारतीय सेना और उद्योग को बधाई दी है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. समीर वी. कामत ने मिसाइल को भारतीय सेना में शामिल करने के लिए तैयार करने के लिए सभी हितधारकों के प्रयासों की सराहना की।

प्रयागराज, 14 जनवरी। महाकुंभ के पहले अमृत (शाही) स्नान में मंगलवार को 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। शाही स्नान सुबह 6 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे खत्म

और बस स्टैंड की ओर जाने वाली सड़कों पर भारी भीड़ देखी गई। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर पैर रखने की जगह नहीं है। लोगों को हॉल में रोका गया है। ट्रेनों के हिसाब से उन्हें प्लेटफार्म पर भेजा जा रहा है।

सुबह 6 बजे से शाही (अमृत) स्नान शुरु हुआ और शाम 6 बजे तक चला, तलवार व त्रिशूल लिए हुए सन्यासी हर-हर महादेव का उद्घोष करते हुए घाट पर पहुंचे।

स्नान के बाद लोगों ने वापसी शुरु की तो रेलवे प्लेटफॉर्म और बस स्टैंड तक जाने वाली सड़कों पर भारी भीड़ हो गई। लोगों को अब ट्रेन व बस के समय के आधार पर ही आगे भेजा जा रहा है।

ट्रेन व बसों में भारी भीड़ के कारण कई श्रद्धालु लौट नहीं पाए हैं और होटल, धर्मशाला व रैन बसेरे फुल होने के कारण उन्हें सड़कों पर ही सोना पड़ रहा है।

हुआ। इस दौरान, जून अखाड़ा समेत सभी 13 अखाड़ों के संतों ने स्नान किया। स्नान के बाद, लोगों ने प्रयागराज से लौटना शुरू कर दिया है। रेलवे स्टेशन पर भेजा जा रहा है। रेलवे के अमित सिंह ने बताया कि आज सुबह से अब तक 55 महाकुंभ स्पेशल ट्रेनें रवाना की (शेष अंतिम पृष्ठ पर)



मंगलवार को मकर संक्रांति पर महाकुंभ में प्रथम शाही (अमृत) स्नान में सबसे पहले जून अखाड़ा के संतों ने संगम में स्नान किया। तलवार और त्रिशूल लिए हुए साधु संत घोड़े पर सवार होकर घाट पर पहुंचे। जून अखाड़ा के बाद, 12 अन्य अखाड़ों के संतों ने संगम स्नान किया।

'2026 करोड़ रु. के नुकसान का कोई जवाब नहीं है केजरीवाल के पास'

आबकारी नीति पर सीएजी रिपोर्ट को केजरीवाल के खिलाफ चुनावी मुद्दा बना रही है भाजपा

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 14 जनवरी। अरविंद केजरीवाल और उनकी आप सरकार के पास राजकोष को हुये उस 2026 करोड़ रूपए के नुकसान का कोई जवाब नहीं है, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (सीएजी) की 14 रिपोर्टों में बताया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस बात को लेकर आप सरकार को फटकार लगाई है कि उसने सीएजी की रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में पेश नहीं की।

25 साल से दिल्ली की सत्ता से दूर भाजपा को उम्मीद है कि इस चुनाव में 12 साल पुरानी आप सरकार को वह अवश्य ही मात दे देगी। जिस तरह आप सरकार के खिलाफ सीएजी की रिपोर्ट बड़ा मुद्दा बन रही है, ठीक इसी प्रकार केजरीवाल और अन्ना हजारे ने सीएजी रिपोर्ट के आधार पर डॉ. मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार को घेरा था, जिसका भाजपा ने भरपूर लाभ उठाया।

अब आप भी उसी स्थिति का सामना कर रही है। हालांकि, आप इस बार सीएजी रिपोर्ट की प्रामाणिकता पर सवाल उठा रही है।

आप इस बात से परेशान है कि उच्च न्यायालय ने आप सरकार द्वारा सीएजी रिपोर्ट्स छिपाने पर सवाल खड़े किये हैं। यहाँ यह स्मरण दिलाया उचित होगा कि इसी बिन्दु पर केजरीवाल और अन्ना हजारे ने तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार को घेरा था। तत्कालीन सीएजी विनोद राय ने निराधार रिपोर्टों के लिये 78 साल बाद सार्वजनिक रूप से माफी माँगी थी, जबकि मोदी सरकार ने उन्हें 2016 में बैंकिंग बोर्ड ब्यूरो का चेयरमैन बनाकर पुरस्कृत किया था। कांग्रेस नेता इस बात को लेकर चकित थे कि उनकी पार्टी द्वारा तत्कालीन यूपीए सरकार के खिलाफ किये गये झूठे दुष्प्रचार के लिये केजरीवाल ने माफी नहीं माँगी थी। आप नेता जोर देकर कह रहे हैं कि सीएजी रिपोर्ट जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री तथा उपराज्यपाल में से किसी ने भी इस बात का सत्यापन नहीं किया है और न सीएजी ने ही कोई स्पष्टीकरण दिया है।

5 फरवरी को होने वाले चुनाव 12 साल से शासन कर रही आम आदमी पार्टी की सरकार के इर्द-गिर्द केन्द्रित हैं, जबकि भाजपा पिछले 25 साल से दिल्ली की सत्ता से बाहर है। सभी लोगों की नज़रें इस बिन्दु पर लगी हुई हैं कि क्या केजरीवाल भाजपा की हिन्दुत्व की राजनीति के साथ इस चुनावी लड़ाई में हैट्रिक लगा पाएंगे।

जहाँ आप, सत्ता-विरोधी प्रवृत्ति का सामना कर रही है, क्योंकि लोग उससे नाराज हैं और लोगों में उसकी सरकार में रुचि नहीं रही है, सभी लोगों की नज़रें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या भाजपा, आप को मात दे देगी, जिसने भाजपा को 2015 में 3 सीटों तथा 2020 के चुनाव में 8 सीटों तक सीमित कर दिया था। 2015 से लेकर

अब तक, कांग्रेस, जो 15 साल सत्ता में रही थी, एक भी सीट नहीं जीत पाई है। आप नेता जोर देकर कह रहे हैं कि सीएजी रिपोर्ट जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री तथा उपराज्यपाल में से किसी ने भी इस बात का सत्यापन नहीं किया है और न सीएजी ने ही कोई स्पष्टीकरण दिया है।

आज नए मुख्यालय में शिफ्ट करेगी कांग्रेस

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 14 जनवरी। हरियाणा व महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद कठिन चुनावी चुनौतियों का सामना कर रही कांग्रेस पार्टी बुधवार को अपने नए राष्ट्रीय मुख्यालय, इंदिरा भवन में शिफ्ट होगी। यदि दीवारें बात कर सकती तो, 24, अकबर रोड, बंगला, ब्रिटिश राज, नया हैड क्वार्टर, 9ए कोटला रोड का नामकरण इंदिरा भवन किया गया है।

आगामी बजट में कई टैक्स राहतें मिलने की संभावना

जानकार सूत्रों ने बताया, प्रधानमंत्री कार्यालय में बजट पर चर्चा में यह संभावना उभरी

महाराष्ट्र व हरियाणा विधानसभा चुनावों में जीत से उत्साहित भाजपा सुधार कार्यक्रमों व "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" के संबंध में बजट में मजबूत रुख अपनाता चाहती है। भाजपा हल्कों में भी मांग उठ रही है कि मध्यम वर्ग को इन्कम टैक्स में राहत दी जाए, ताकि मांग और उपभोग में वृद्धि हो। विशेषज्ञों का कहना है कि टैक्स का बोझ कम होने से शहरों में मांग बढ़ेगी।

बजट में कॉरपोरेट टैक्स और टीडीएस प्रणाली का सरलीकरण किए जाने की भी संभावना बताई जा रही है।

जानकार सूत्रों ने बताया, जो कदम उठाए जाने पर विचार हो रहा है, उनमें मध्यम वर्ग को टैक्स राहत देने और उद्योग वर्ग को बाहरी वातावरण के प्रभाव से बचाने, टैरिफ सम्बंधी उपाय करने से लेकर रोजगार सृजन और निजी निवेश बढ़ाना प्रमुख हैं। "गत सप्ताह प्रधानमंत्री कार्यालय में बजट पर चर्चा हुई थी और आगे भी चर्चा होगी। महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनावी जीत से उत्साहित नरेन्द्र मोदी सरकार बजट में मजबूती का संदेश देना चाहती है कि सुधार कार्यक्रम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जारी रखा जाएगा। सूत्रों ने कहा, चर्चा शुरू हो गई है और सरकार

हाई कोर्ट से वापस मिल पायी साइबर फ्रॉड में फ्रीज राशि

जयपुर, 14 जनवरी। सायबर फ्रॉड में गई राशि को भले ही बैंक में फ्रीज कर दिया हो, लेकिन पीडित युवती को उसे वापस लेने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट तक संघर्ष करना पड़ा। अब हाईकोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिए हैं कि वह संबंधित बैंक को आदेश देकर याचिकाकर्ता को राशि दिलाए। हालांकि अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता निचली अदालत में यह अंडरटेकिंग दे कि यदि किसी तीसरे पक्ष ने इस राशि पर क्लेम किया तो वह राशि जमा करा देगा और अदालत उस पर

याचिकाकर्ता की राशि तीन साल से बैंक में फ्रीज पड़ी थी पुलिस ने भी फाइनल रिपोर्ट के बाद याचिकाकर्ता को राशि देने में कोई आपत्ति नहीं की थी। फैसला करेगी। जस्टिस अनूप कुमार ढंड को एकलपीठ ने ये आदेश वृषिता मेहता को याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के साथ साल 2022 में साइबर फ्रॉड हुआ था। इसके चलते उससे 99,999 रूपए बंधन बैंक में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)